

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या-207 / 2017 / झालावाड़

1. बालकृष्ण आत्मज श्री श्यामबिहारी लाल निवासी मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़।
2. मुरलीमनोहर आत्मज बालकृष्ण निवासी मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़। ...प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार उप-पंजीयक, पीडावा जिला झालावाड़।
2. भूपेन्द्र कुमार भंसाली आत्मज स्व. श्री जमनालाल (कायम मुकाम स्व. जमनालाल) निवासी रायपुर तहसील पीडावा जिला झालावाड़। ...अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री नव्वूराम, सदस्य

उपस्थित :

श्री सुमित जैन

अभिभाषक

श्री आर.के.अजमेरा

उप-राजकीय अभिभाषक

अनुपस्थित

....प्रार्थीगण की ओर से

....अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

....अप्रार्थी सं. 2

निर्णय दिनांक : 10.04.2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थीगण द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) कोटा (जिसे आगे 'कलक्टर' कहा गया है) के आदेश दिनांक 14.05.2015 प्रकरण संख्या 551 / 2009 के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उप-पंजीयक पीडावा द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि बालकृष्ण पुत्र श्री श्यामबिहारी निवासी मनोहरथाना जिला झालावाड़ एवं अन्य द्वारा एक विक्रिय पत्र श्री जमनालाल पुत्र श्री रखबचन्द जाति जैन निवासी रायपुर तहसील पीडावा जिला झालावाड़ से आराजी खसरा नम्बर 2004 में रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा में से 1 बीघा 2 बिस्वा का क्रय किया गया जिसका दस्तावेज उप पंजीयक कार्यालय पीडावा में क्रम संख्या 2005000131 दिनांक 19.02.2005 को पंजीबद्ध कराया गया। अधीनस्थ न्यायालय में उपपंजीयक पीडावा द्वारा महालेखाकार जयपुर द्वारा निरीक्षण अवधि 04/02 से 12/05 में कमी मालियत के

२३

लगातार.....2

आक्षेप के आधार पर रेफरेन्स प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में अपना जवाब प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स स्वीकार करते हुए कमी मुद्रांक राशि 3,23,495/- रु., पंजीयन शुल्क 20,490/- रु. व शास्ति 115/- कुल 3,44,100/- रु. वसूल किये जाने के आदेश दिये गये जिससे अप्रसन्न होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर सुनी गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। प्रकरण में विचाराधीन बिन्दु एवं तथ्यों को देखते हुए उभयपक्ष की सहमति पर प्रकरण का इसी स्तर पर निस्तारण किया जाना उचित मानते हुए बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नॉन स्पीकिंग एवं साईक्लोस्टाईल ऑर्डर है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर कोई विचार नहीं किया गया है व न ही रेफरेन्स को मानने के कारण अंकित किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि जेरनिगरानी आदेश में विवादित विक्रय पत्र से जो कृषि भूमि क्रय की गई है उस पर निगराकार ने विक्रय पत्र पंजीयन कराते समय ही तत्कालीन जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित दरों से लगभग दुगुनी दर पर मुद्रांक अदा कर दस्तावेज पंजीयकृत कराया था जिसे बिना किसी आधार के मात्र कायम पर व्यवसायिक उपयोग की होना मानकर कमी मुद्रांक, पंजीयन शुल्क व पेनल्टी की राशि वसूल किये जाने के आदेश प्रदान कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि निगराकार द्वारा दिनांक 19.02.05 को खसरा नं. 2004 की 1 बीघा 2 बिस्वा कृषि भूमि क्रय की गई थी तत्पश्चात उक्त भूमि में से 2695 वर्गमीटर भूमि को विधिवत जिला कलक्टर झालावाड से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (पेट्रोल पम्प) संपरिवर्तित कराया है। जिसका संपरिवर्तन आदेश दिनांक 20.05.05 को जारी होने के पश्चात उक्त संपरिवर्तित भूमि को 19 वर्ष 11 माह के लिये रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को पंजीकृत लीज एग्रीमेन्ट द्वारा 1/- रु. मासिक किराया (लीज रेन्ट) पर दिया गया है। उपपंजीयक महोदय ने द्वारा रेफरेन्स के विरुद्ध जाकर बिना किसी आधार के निगराकार के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर एकपक्षीय आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है क्योंकि गैर निगराकार 1 ने अधीनस्थ न्यायालय को रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करने हेतु रेफरेन्स किया था

किन्तु इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को तलब किये बिना ही उसके स्थान पर निगराकार के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर व सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान भी रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को तलब नहीं कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित सम्पत्ति का मूल्यांकन अंकित किये बिना मात्र मांग राशि अंकित कर निगराकार को नोटिस जारी कर दिया जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निगराकार द्वारा प्रस्तुत जवाब में विवादित सम्पत्ति का मूल्यांकन अंकित नहीं होना व मूल्यांकन का आधार उपलब्ध नहीं होने की आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने निगराकार को ना तो समपत्ति का मूल्यांकन बताया और ना ही मूल्यांकन आधार उपलब्ध कराया। यही नहीं जैर निगरानी आदेश में भी सम्पत्ति का मूल्यांकन अंकित किये बिना ही निगराकार के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर आदेश पारित कर दिया जो आर्बिटरी परवरस व न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

5. राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानी खारिज की जावें।

6. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने की दृष्टिगत स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।

7. निगरानी में निगरानीकर्ता का मुख्य आधार यह है कि कलक्टर मुद्रांक कोटा का निर्णय एक नॉन स्पीकिंग एवं साईक्लोस्टाईल ऑर्डर है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विचार नहीं किया है व न ही रेफरेन्स में तथ्यों को स्वीकार करने के कारणों का उल्लेख किया है।

रेफरेन्स ऑडिट आक्षेप के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निगरानीधीन निर्णय द्वारा रेफरेन्स के तथ्यों को स्वीकार किया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने न तो रेफरेन्स के तथ्यों की राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 के अनुसार जांच की है व न ही अपने निर्णय में तथ्यों के संबंध में कोई विवेचना या विश्लेषण किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में तर्क, कारण व विवेचना का अभाव है। अधीनस्थ

न्यायालय का दायित्व बनता है कि उसके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं की विवेचना करने के उपरान्त ही उन्हें मानने या न मानने पर तथ्यों पर आधारित अपना मत प्रकट करते, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश/निर्णय के विरुद्ध अपील होने पर सम्बन्धित न्यायालय अपना निर्णय पारित करें कि अवर अधिकारी का निर्णय न्याय संगत है अथवा नहीं किन्तु प्रस्तुत निगरानी में कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। अपीलीय अधिकारी का दायित्व बनता है कि वह सचेतन मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निष्पक्ष अभिव्यक्ति दें। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ के सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स, कोटा बनाम मैसर्स शुक्ला एड ब्रदर्स (Civil Appeal No. Nil of 2010/S.L.P.(C)No. 16466 of 2009), date 15.4.2010) में पारित किये गये निर्णय के कुछ अंश उद्धृत किया जाना उक्त परिप्रेक्ष्य में समीचीन होगा :—

".... To subserve the purpose of justice delivery system therefore, it is essential that the Courts should record reasons for its conclusions whether disposing of the case at admission stage or after regular hearing."

"A litigant has legitimate expectation of knowing reasons for rejection of his claim/payer. It is then alone, that a party would be in a position to challenge the order on appropriate grounds. As arguments bring things hidden and obscure to the light of reasons, reasoned judgment where the law and factual matrix of the case it discussed provided lucidity and foundation for conclusions or exercise of judicial discretion by the Courts. Reason is the very life of law. When the reason of a law once ceases, the law itself generally cease. Such is the significance of reasoning in any rule of law. Giving reasons furthers the cause of justice as well as avoids uncertainty. As a matter of fact it helps in the observance of law of precedent . Absence of reasons on the contrary essentially introduces an element of uncertainty, dissatisfaction and give entirely different dimensions to the questions of law raised before the higher appellate Courts. When reasons are announced and can be weighed, the public can have assurance that process of correction is in place and working. It is requirement of law that correction process of judgments should not only appear to be implemented but also to have been properly implemented. Reasons for an order would ensure and enhance public confidence and would provide due satisfaction to the consumer of justice under our justice dispensation system."

उपरोक्त विधिक धारणा से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है तथा निगरानी का यह आधार स्वीकार योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी की निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन निर्णय दिनांक 14.05.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए एवं राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 की पालना करते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.05.2017 को पेश हों।

9. निर्णय सुनाया गया।

(नृथूराम)
सदस्य